

**File No.1(11)/2018-Coord.**

No.1(11)/2018-Coord.  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Public Enterprises

Block No.14, CGO Complex,  
Lodi Road, New Delhi – 110003  
Dated the 20 October, 2021

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject:- Monthly summary of Principal activities of Department of Public Enterprises for circulation to the Council of Ministers – regarding.**

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat's O.M. No.1/26/1/2018-Cab dated 17<sup>th</sup> August, 2018 on the subject mentioned above and to enclose monthly summary pertaining to the Department of Public Enterprises for the month of September, 2021.

(Naresh Kumar)  
Under Secretary to the Govt. of India  
T.No.24366820  
e-mail : naresh.kr68@nic.in

Encl : As Above

To

1. All Members of the Council of Ministers.

Copy to:-

1. All Secretaries to the Govt. of India's Ministries/ Departments.
2. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3. PPS to Secretary(PE)/ PPS to AS(RKC)/ PS to JS(SKJ)/ Sr.PPS to Adviser(AK)/ PA to Adviser(PK).
4. Sr. Technical Director (NIC) for uploading on the DPE website.

**Ministry of Finance**  
**Department of Public Enterprises**  
**Monthly Summary for the Cabinet for the month of September, 2021**

An updated on the principal activities and key initiatives under taken by the Department of Public Enterprises (DPE) during the month of September, 2021 is indicated below:-

**1. CAPEX targets:**

The information relating to annual CAPEX targets of ₹5,95,138 crores and its achievement in respect of select CPSEs and other government organisations up to the month of September 2021 was submitted to PMO on 5<sup>th</sup> October, 2021. Against an estimated expenditure of ₹5.95 lakh crores (approx.), achievement is ₹2.19 lakh crores (approx.) or about 37%. Information in relation to Railway Board is upto 31.8.2021.

**2. CCEA Notes:**

Two draft CCEA Notes of other Ministries/Departments were examined by DPE and comments furnished thereon to Department of Expenditure to obtain approval of Hon'ble FM.

**3. Parliamentary Committee on Public Undertakings (COPU):**

A sitting of the Committee on Public Undertakings (COPU) was held on 20<sup>th</sup> September, 2021 on "Examination of Corporate Governance in CPSUs". During the sitting, a presentation was made before the Committee wherein it was highlighted that the monitoring of compliance on corporate governance norms by CPSEs has been incorporated in the MoU framework. As per the framework, negative marking has been prescribed in case of non-compliance by CPSEs in respect of corporate governance norms which also includes compliance of various government priorities.

**4. MoU Framework:**

- i. Two meetings of IMC were organised during the month on Sectoral Benchmarking for the MoU of CPSEs for the year 2021-22 and the work on freezing the exercise completed.
- ii. A meeting of High Powered Committee under the Chairmanship of the Cabinet Secretary was held on 23.09.2021 regarding MoU evaluation of CPSEs for the year 2019-20 and the Gradings finalised.

**5. Ratna Status:**

A meeting of Inter-Ministerial Committee was held to consider the proposal of Ministry of Power for grant of Maharatna Status to Power Finance Corporation Limited on 16<sup>th</sup> September, 2021; followed by meeting of Apex Committee under the Chairmanship of Cabinet Secretary on 23<sup>rd</sup> September, 2021. The Apex Committee approved the proposal.

#### **6. Corporate governance of CPSEs:**

- i. 110 below Board level posts were exempted from the rule of absorption in Mumbai Railway Vikas Corporation (MRVC) for a period of 3 years beyond 30.6.2021.
- ii. Two meetings of Search Committee was held to recommend names for filling up of 162 & 139 positions of non-official Directors on the Board of various CPSEs on 13.09.2021 and 22.09.2021 respectively.
- iii. Guideline regarding payment of Performance Related Pay (PRP) in the absence of Independent Director, the Chairman of the Remuneration Committee, was issued on 01.09.2021.

#### **7. Inter-Ministerial Meetings and Special Campaign:**

- i. Seven IMG/CGD meetings were held during the month.
- ii. A review meeting under the Chairmanship of Secretary, DPE was held on 2<sup>nd</sup> September, 2021 with the administrative Ministries/ Departments of 22 CPSEs under closure.
- iii. A presentation was made to the FM on Closure/Privatisation Guidelines for non-strategic sector CPSEs.
- iv. Secretary, DPE chaired a meeting on 27<sup>th</sup> September, 2021 with CEO, GeM and 25 top procuring CPSEs to discuss issues relating to procurement by CPSEs through GeM and steps to be taken to enhance procurement by CPSEs through GeM.
- v. As per the guidelines issued by Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), targets were set for Special Campaign during 2<sup>nd</sup> October to 31<sup>st</sup> October, 2021 for disposal of pending matters.

#### **8. Training programmes/workshops:**

- i. DPE organised six training programmes and one workshop through online mode on various issues related to functioning of CPSEs for benefit of officials of CPSEs.
- ii. Department of Public Enterprises (DPE) in association with the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) organised a one-day orientation programme for Directors of CPSEs for capacity building of Directors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on 22<sup>nd</sup> September, 2021 through online mode. 102 CPSEs executives participated in the programme. The participating Directors were sensitised about their role in Corporate Governance and responsibilities in the context of Companies Act, 2013, risk management, etc.

\*\*\*\*\*

**वित्त मंत्रालय**  
**लोक उद्यम विभाग**  
**मंत्रिमंडल के लिए सितम्बर, 2021 माह हेतु मासिक सारांश**

सितम्बर, 2021 माह के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में एक अद्यतन रिपोर्ट (अपडेट) निम्नवत है:-

**1. कैपेक्स लक्ष्य:**

सितम्बर, 2021 माह तक के लिए 5,95,138 करोड़ रुपये के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य और चयनित सीपीएसईज़ और अन्य सरकारी संगठनों की उपलब्धि से संबंधित जानकारी 5 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है। 5.95 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित व्यय के मुकाबले, उपलब्धि 2.19 लाख करोड़ रुपये (लगभग) या लगभग 37% है। रेलवे बोर्ड के संबंध में सूचना दिनांक 31.08.2021 तक है।

**2. सीसीईए नोट्स:**

टिप्पणियों के लिए प्राप्त अन्य मंत्रालयों/विभागों के दो मसौदा सीसीईए नोट्स की लोक उद्यम विभाग द्वारा जांच की गई और माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग को टिप्पणियां भेजी गईं।

**3. सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति (सीओपीयू):**

"सीपीएसयूज़ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जांच" पर 20 सितंबर, 2021 को सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान समिति के समक्ष एक प्रजेंटेशन दिया गया जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सीपीएसईज़ द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों पर अनुपालन की निगरानी को एमओयू फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। ढांचे के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के संबंध में सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन न करने के मामले में नकारात्मक अंकन निर्धारित किया गया है जिसमें विभिन्न सरकारी प्राथमिकताओं का अनुपालन भी शामिल है।

**4. एमओयू फ्रेमवर्क:**

- i. वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसईज़ के एमओयू के लिए सेक्टरल बेंचमार्किंग पर माह के दौरान आईएमसी की 2 बैठकें आयोजित की गईं और इस एक्सरसाइज़ को फ्रीज करने का काम पूरा किया गया।
- ii. वर्ष 2019-20 के लिए सीपीएसईज़ के एमओयू मूल्यांकन और ग्रेडिंग को अंतिम रूप देने के संबंध में दिनांक 23.09.2021 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई।

**5. रत्न स्थिति:**

दिनांक 16 सितंबर, 2021 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा देने के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक हुई; इसके बाद दिनांक 23 सितंबर, 2021 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक हुई। शीर्ष समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

## 6. सीपीएसईज़ का कारपोरेट गवर्नेंस:

- i. बोर्ड स्तर के नीचे के 110 पदों को मुंबई रेलवे विकास निगम (एमआरवीसी) में दिनांक 30.06.2021 के बाद 3 साल की अवधि के लिए आमेलन के नियम से छूट दी गई थी।
- ii. विभिन्न सीपीएसईज़ के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के 162 और 139 पदों को भरने के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए सर्च समिति की दो बैठकें दिनांक 13.09.2021 और 22.09.2021 को आयोजित की गईं।
- iii. स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष-पारिश्रमिक समिति की अनुपस्थिति में कार्य-निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) के भुगतान के संबंध में दिशानिर्देश दिनांक 01.09.2021 को जारी किया गया था।

## 7. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और विशेष अभियान:

- i. माह के दौरान 7 आईएमजी/सीजीडी की बैठकें आयोजित की गईं।
- ii. सचिव, डीपीई की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक दिनांक 2 सितंबर, 2021 को बंद होने के अधीन 22 सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ आयोजित की गई थी।
- iii. वित्त मंत्री के समक्ष गैर सामरिक क्षेत्र सीपीएसई के लिए क्लोजर/निजीकरण के दिशा-निर्देशों पर प्रजेंटेशन दिया गया।
- iv. सचिव, डीपीई ने दिनांक 27 सितंबर, 2021 को सीईओ, जीईएम और 25 शीर्ष खरीद करने वाले सीपीएसईज़ के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जीईएम के माध्यम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद से संबंधित मुद्दों और जीईएम के माध्यम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई।
- v. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लंबित मामलों के निस्तारण के लिए दिनांक 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान विशेष अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

## 8. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

- i. डीपीई ने सीपीएसईज़ के अधिकारियों के लाभ के लिए सीपीएसईज़ के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से छह प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक कार्यशाला का आयोजन किया।
- ii. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के सहयोग से ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिनांक 22 सितंबर, 2021 को केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए सीपीएसईज़ के निदेशकों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीपीएसईज़ के 102 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागी निदेशकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस में उनकी भूमिका और कंपनी अधिनियम, 2013, जोखिम प्रबंधन आदि के संदर्भ में जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया गया।

\*\*\*\*\*